Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-14 16-31 जुलाई, 2025 (पाक्षिक) ₹20

'भाजपा विचार आधारित पार्टी है'

'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना'

'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो'

'द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सचिया मिराबिलिस'

'द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस'

भारत समावेशी विकास, पारस्परिक समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) से 06 जुलाई, 2025 को दिल्ली एवं हरियाणा के तीन जिला कार्यालयों का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

सरगुजा (छत्तीसगढ़) में 07 जुलाई, 2025 को 'भाजपा सांसद–विधायक प्रशिक्षण वर्ग' के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

हिमाचल प्रदेश में 09 जुलाई, 2025 को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

तिरुवनंतपुरम (केरल) में 12 जुलाई, 2025 को 'विकसित केरलम् सम्मेलन' में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते केरल भाजपा के नेतागण

निजामाबाद (तेलंगाना) में 29 जून, 2025 को आयोजित 'किसान महासम्मेलन' में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते तेलंगाना भाजपा के नेतागण

हैदराबाद में 04 जुलाई, 2025 को श्री अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती समारोह में दीप प्रज्वलित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 द्विपक्षीय व बहुपक्षीय हितों का संवर्धन, समावेशी विकास और शांति व सुरक्षा के प्रति समर्पित रही प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 से 9 जुलाई के बीच पांच देशों घाना, त्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की 8 दिवसीय...

14 भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है कि यह विचार आधारित पार्टी है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 6 जुलाई...

16 राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक है : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 जून, 2025 को तेलंगाना के...

17 'भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना समय 'विकसित केरलम्' के लिए समर्पित करना है'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 12 जुलाई, 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा केरल प्रदेश के...

18 'केंद्र सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जुलाई, 2025...

लेख

डिजिटल इंडिया का एक दशक / **नरेन्द्र मोदी** 24

जब सरकार चिंता करती है, तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रगति करती हैं / **जगत प्रकाश नड्डा** 26

महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का उपयोग / **अन्नपूर्णा देवी** 28

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: राष्ट्रीय एकता के अखंड पुजारी / **शिवप्रकाश** 30

मन की बात

आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी-न-किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं: नरेन्द्र मोदी 33

अन्य

नए भाजपा प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा 19

भारत की आर्थिक प्रगति 20

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को दी मंजूरी 23

कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी 23

कमल पुष्प 23

भाजयुमो ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 100 प्रतीकात्मक संसद सभाएं आयोजित की 27

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है: नरेन्द्र मोदी 31

'विकसित भारत निर्माण' के लिए मार्गदर्शित करनेवाला संवाद 32

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

अलग-अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बन रहे हैं, जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। देश के नौजवानों ने रोजगार पाने के साथ-साथ कई सेक्टर में रिकॉर्ड भी बनाकर दिखाया है!

(12 जुलाई, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित वर्ग स्थल, कमलेश्वरपुर में देशव्यापी अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' के अंतर्गत वृक्षारोपण कर पार्टी के ऐतिहासिक कालक्रम व भाजपा सरकार की कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 'विकसित भारत' निर्माण को संकल्पित यह प्रदर्शनी भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं को सेवापथ पर निरंतर अग्रसर रहने की दृष्टि से प्रेरणास्पद है। (07 जुलाई, 2025)

अमित शाह

मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को रेहड़ी वालों तक भी पहुंचाया। विरासत और विकास का ऐसा अद्भुत संगम कहीं और नहीं दिखेगा।

(14 जुलाई, 2025)

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता से सरकार ने 2016 में Government E-Marketplace (GeM) की शुरुआत की, जो आज वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सार्वजनिक ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। मुझे गर्व है कि इसकी विकास यात्रा में रक्षा मंत्रालय की अहम भूमिका रही है।

(07 जुलाई, 2025)

बी.एल. संतोष

श्री रवीन्द्र चव्हाण को महाराष्ट्र भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई! संगठन में गहरी पैठ रखने वाले, जमीनी स्तर पर काम करने वाले और जमीनी स्तर पर सक्रिय यह कार्यकर्ता पार्टी को 'विकसित महाराष्ट्र' के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाएंगे।

(01 जुलाई, 2025)

नितिन गडकरी

हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सचिया मिराबिलिस' से सम्मानित होने पर गर्व महसूस करते हैं। यह सम्मान उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं मजबूत वैश्विक गठबंधन बनाने के प्रति उनके समर्पण से प्रेरित है। यह भारत और नामीबिया के बीच गहरी होती मित्रता एवं सहयोग को भी दर्शाता है, यह हमारी साझा यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण है। (09 जुलाई, 2025)

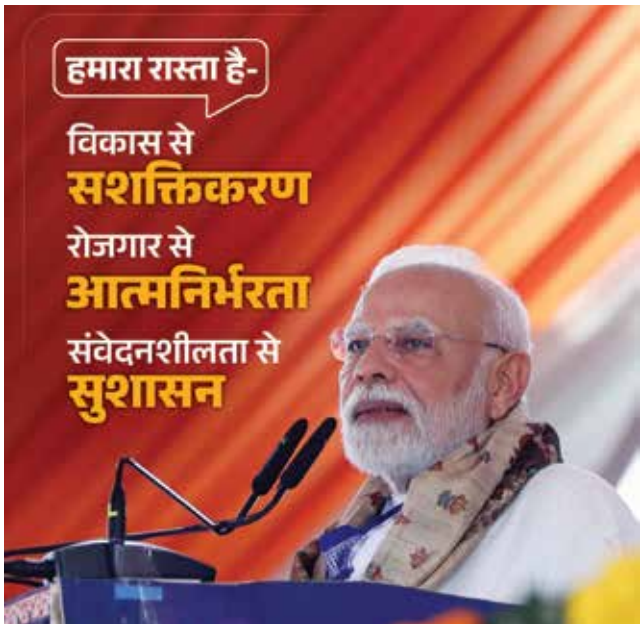

संपादकीय

'वसुधैव कुटुम्बकम्' मंत्र के लिए प्रतिबद्ध भारत

आज जब भारत 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए आगे बढ़ चला है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूरे विश्व में भारत की शांति, विकास एवं परस्पर सहयोग का संदेश दे रहे हैं। भारत आज पूरे विश्व में आशा एवं विश्वास का संचार करते हुए नई आकांक्षाओं के दीप जला रहा है तथा सभी देशों के साथ सुदृढ़ भागीदारी स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाल ही में संपन्न घाना, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया के साथ-साथ 17वें ब्रिक्स में भागीदारी के लिए आठ दिवसीय यात्रा ने इन देशों के साथ संबंधों में एक नई ऊर्जा भरी है। यह यात्रा व्यापार, रक्षा, डिजिटल एवं महत्वपूर्ण खनिज, वैश्विक डिजिटल, जनहितकारी यूपीआई के प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक एवं भारतवंशियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे परस्पर विश्वास को और अधिक बल मिला है तथा सभी देश एक दूसरे के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी बन गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी आठ दिवसीय यात्रा की शुरुआत 2 जुलाई, 2025 को घाना से किया। इस यात्रा के दौरान फिनटेक, पारंपरिक औषधि सहित द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से बढ़ाने की दिशा में काफी बल मिला। घाना संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग एवं समावेशी विकास पर जोर दिया। घाना ने प्रधानमंत्री जी को 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया। 4 जुलाई, 2025 को ट्रिनिडाड एवं टॉबैगो में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवा सशक्तीकरण के लिए 2000 लैपटॉप का सहयोग तथा भारतवंशियों के लिए ओसीआई पात्रता के विस्तार की घोषणा की। पिछले 26 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ट्रिनिडाड एवं टोबैगो की पहली यात्रा थी। भारत-कैरिबियन विरासत के 180 वर्ष पर प्रधानमंत्री ने वहां संसद को संबोधित किया तथा ऊर्जावान भारतवंशियों से जीवंत संवाद किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा से दोनों देशों में परस्पर विश्वास एवं सद्भावना के नए वातावरण का निर्माण हुआ है। महत्वपूर्ण खनिजों, विशेषकर लिथियम के साथ-साथ ऊर्जा, औषधियों, अंतरिक्ष तथा रक्षा में सहयोग पर चर्चा हुई। अर्जेंटीना सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 57 वर्षों में पहली यात्रा रही। श्री मोदी ने ब्राजील में शिखर वार्ता को संबोधित करते हुए वैश्विक शासन सुधार, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा एवं जिम्मेदार एआई को रेखांकित किया तथा 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' तथा इसके विरुद्ध सामूहिक युद्ध लड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। ब्राजील में उन्हें 'द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया।

नामीबिया की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। भारत की यूपीआई को लाइसेंस देने वाला नामीबिया पहला देश बन गया। यह भारत की 'डिजिटल-डिप्लोमेसी' की सफलता को दर्शाता है। इस दौरान रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, कृषि एवं शिक्षा पर विशेष चर्चा हुई। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सचिया मिराबिलिस' से विभूषित किया गया। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन में भी भारत ने आतंकवाद तथा वैश्विक शासन में सुधार तथा पहलगाम आतंकी हमले की निंदा पर सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की।

> **पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में न केवल अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं, बल्कि दुनिया के हर देश में अपने संबंधों को और अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने में सफल हुआ है**

पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में न केवल अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं, बल्कि वह दुनिया के हर देश में अपने संबंधों को और अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने में सफल हुआ है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत आज अधिकतर देशों का महत्वपूर्ण मित्र बन गया है तथा इसके वैश्विक योगदान के महत्व को पूरे विश्व में स्वीकारा एवं सराहा जा रहा है। 'विश्वमित्र' के रूप में भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' मंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। आज जब संपूर्ण राष्ट्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, भारत वैश्विक शांति, परस्पर विश्वास एवं सद्भाव तथा विकास एवं स्थायित्व के लिए मजबूत भागीदारी के लिए संकल्पबद्ध है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

प्रधानमंत्री ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया की यात्रा की तथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया

द्विपक्षीय व बहुपक्षीय हितों का संवर्धन, समावेशी विकास और शांति व सुरक्षा के प्रति समर्पित रही प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 से 9 जुलाई के बीच पांच देशों घाना, त्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की 8 दिवसीय यात्रा की। इस मैराथन यात्रा के मध्य श्री मोदी ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 6-7 जुलाई को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस अभूतपूर्व यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 3 देशों घाना, त्रिनिडाड और टोबैगो तथा नामीबिया की संसद को संबोधित किया और उन्हें 4 राष्ट्रों घाना, त्रिनिडाड और टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री की 5 देशों व 6 शहरों की इस अहर्निश यात्रा ने इन देशों के साथ न केवल भारत के ऐतिहासिक संबंधों को और सुदृढ़ किया, बल्कि कृषि, निवेश, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण जैसे कई प्रमुख विषयों में घनिष्ठ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही, अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा की, जिसमें वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बुलंद करना, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं

घाना की यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2-3 जुलाई को राष्ट्रपति श्री जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका के देश घाना की राजकीय यात्रा की। घाना के राष्ट्रपति श्री महामा ने श्री मोदी का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की घाना की यह यात्रा तीन दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी।

घाना के राष्ट्रपति श्री जॉन ड्रामानी महामा से भेंट: द्विपक्षीय हितों व संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 जुलाई को घाना के राष्ट्रपति श्री जॉन ड्रामानी महामा से भेंट की। दोनों नेताओं ने सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में भेंट की और व्यापक बातचीत की। वे संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने भारत और घाना के बीच मधुर और समय

घाना के बीच ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया, जो स्वतंत्रता के लिए साझा संघर्षों और लोकतंत्र तथा समावेशी विकास के लिए समान प्रतिबद्धता के माध्यम से बना है।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और साइबर खतरों जैसी दबावपूर्ण वैश्विक चुनौतियों को भी रेखांकित किया और वैश्विक शासन में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज का आह्वान किया।

चार समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) पर समझौताः कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विरासत में अधिक सांस्कृतिक समझ और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और घाना मानक प्राधिकरण (जीएसए) के बीच समझौताः मानकीकरण, प्रमाणन और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से।
- घाना के पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान (आईटीएएम) और भारत के आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) के बीच समझौताः पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में सहयोग करना।
- संयुक्त आयोग की बैठक पर समझौताः उच्च स्तरीय संवाद को संस्थागत बनाना और नियमित आधार पर द्विपक्षीय सहयोग तंत्र की समीक्षा करना।

के अनुरूप संबंधों की पुष्टि की और व्यापार एवं निवेश, कृषि, क्षमता निर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के स्वरूपों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा की।

दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों सहित आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रपति श्री महामा को उनके समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया।

घाना की संसद को संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 जुलाई को घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह संबोधन भारत-घाना संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो दोनों देशों को एकजुट करने वाले परस्पर सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत और

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने घाना का राष्ट्रीय सम्मान ग्रहण किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनकी असाधारण शासन कला और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व में योगदान के कारण घाना के राष्ट्रपति श्री जॉन ड्रामानी महामा ने 3 जुलाई को घाना के राष्ट्रीय सम्मान 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस विशेष सम्मान के लिए घाना की जनता और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराएं साझेदारी को आगे बढ़ाती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मित्रता को और गहरा करता है तथा द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने की नई जिम्मेदारी उन पर डालता है।

प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद एवं टोबैगो यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य की प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद-बिसेसर के निमंत्रण पर 3 से 4 जुलाई तक त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होने के कारण यह ऐतिहासिक यात्रा रही। इसके व्यापक महत्व थे, क्योंकि यह 1845 में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। इसने गहरी जड़ें जमाए हुए सभ्यतागत संबंधों, लोगों के बीच जीवंत संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि की, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता का आधार हैं।

त्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक वार्ता

छह समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन के रेड हाउस में त्रिनिडाड और टोबैगो गणराज्य की प्रधानमंत्री श्रीमती कमला परसाद-बिसेसर से भेंट की। दोनों नेताओं ने कृषि, स्वास्थ्य सेवा और औषधि, डिजिटल परिवर्तन, यूपीआई, क्षमता निर्माण, संस्कृति, खेल और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित संभावित सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की। विकास सहयोग भारत-त्रिनिडाड और टोबैगो साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री श्रीमती बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिडाड और टोबैगो की ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करेगी।

दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के लोगों को त्रिनिडाड और टोबैगो द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन और एकजुटता की प्रशंसा की।

दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेता ग्लोबल साउथ के देशों के बीच अधिक एकजुटता के लिए मिलकर काम करने और भारत-कैरिकॉम साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए।

वार्ता के बाद फार्माकोपिया, त्वरित प्रभाव परियोजनाओं, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण और हिंदी तथा भारतीय अध्ययन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) चेयर के लिए छह समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए कई घोषणाएं भी की गईं, जिनमें त्रिनिडाड और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड की पेशकश शामिल है।

त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीनेट के सभापति महामहिम वेड मार्क और सदन के अध्यक्ष महामहिम जगदेव सिंह के निमंत्रण पर 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो (टीएंडटी) की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। टीएंडटी की संसद को संबोधित करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और यह अवसर भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत ने इस पद्धति को अपनी संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। श्री मोदी ने कहा कि इस दृष्टिकोण ने भारत की विविधता को फलने-फूलने और समृद्ध होने तथा सभी विचारों के सह-अस्तित्व तथा संसदीय विमर्शों और सार्वजनिक चर्चाओं को समृद्ध बनाने का अवसर दिया है।

सदन में महिला सांसदों की काफी संख्या में उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने भारत द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदम पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने मानवता के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विश्व समुदाय से शांतिप्रिय समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने वैश्विक शासन में सुधार और ग्लोबल साउथ को उसका हक दिए जाने का आह्वान किया। उन्होंने भारत-कैरिकॉम संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री श्री मोदी 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सम्मानित

पोर्ट ऑफ स्पेन में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ओआरटीटी ने 4 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार 'द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' प्रदान किया। यह उनकी राजनीति कौशल, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं की पैरवी करने तथा भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान के लिए है। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता हैं।

भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से पुरस्कार स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने इस सम्मान को दोनों देशों के बीच मित्रता के स्थायी बंधन को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि ये विशेष संबंध 180 वर्ष पहले देश में आए भारतीयों द्वारा बनाए गए साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हैं।

त्रिनिडाड और टोबैगो में सामुदायिक कार्यक्रम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जुलाई को त्रिनिडाड और टोबैगो में भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित किया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में त्रिनिडाड और टोबैगो की प्रधानमंत्री श्रीमती कमला प्रसाद-बिसेसर को उनके गर्मजोशी भरे स्वागत करने और दोनों देशों के बीच जीवंत और विशेष संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान

के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे समय में त्रिनिडाड और टोबैगो की उनकी ऐतिहासिक यात्रा, जब देश अपने तटों पर भारतीय प्रवासियों के पहले आगमन की 180 वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसे और भी विशेष बनाती है। श्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों की उनके सुगम, सांस्कृतिक समृद्धि और त्रिनिडाड और टोबैगो में उनके अपार योगदान की प्रशंसा की।

अर्जेंटीना यात्रा

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मुलाकात: द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जुलाई को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति श्री हावियर मीलेई से मुलाकात की। कासा रोसाडा पहुंचने पर राष्ट्रपति श्री मीलेई ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 57 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यह भारत-अर्जेंटीना संबंधों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने और अपने प्रतिनिधिमंडल के शानदार आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति श्री मीलेई को धन्यवाद दिया।

दोनों नेताओं ने सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में मुलाकात की। उन्होंने व्यापक चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों, तेल और गैस, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि में ड्रोन के उपयोग, मत्स्य पालन और बिजली पारेषण लाइनों की निगरानी, आईसीटी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, अंतरिक्ष, रेलवे, फार्मा, खेल और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

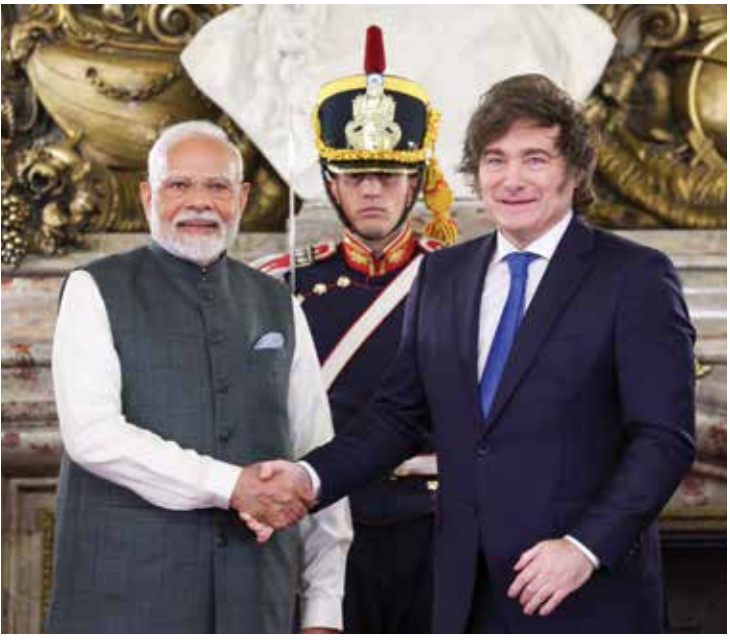

नेताओं ने वर्तमान आर्थिक सहयोग का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोनों पक्षों को वाणिज्यिक सहयोग की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए व्यापार क्षेत्र में विविधता लाने पर काम करने की जरूरत है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के विस्तार पर भी चर्चा की।

श्री मोदी ने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए राष्ट्रपति श्री मीलेई को धन्यवाद दिया और आतंकवाद से लड़ाई में भारत के प्रति अर्जेंटीना की एकजुटता की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने इस खतरे से वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति प्रकट की। उन्होंने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को अधिक से अधिक आवाज देने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के समापन से पहले ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति श्री मीलेई ने अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने राष्ट्रपति श्री मीलेई को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया।

प्रधानमंत्री ने सैन मार्टिन स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जुलाई को अर्जेंटीना की अपनी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत अर्जेंटीना के राष्ट्रपिता जनरल जोस डे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। श्री मोदी ने प्लाजा सैन मार्टिन का भ्रमण किया और स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने जनरल जोस डे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की और अर्जेंटीना तथा कई अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों के मुक्तिदाता के रूप में उनकी स्थायी विरासत को मान्यता दी। भारत उनके योगदान और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों का सम्मान करता है। अर्जेंटीना के नायक के नाम पर नई दिल्ली में एक सड़क हमें उनकी विरासत की याद दिलाती है। यह दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक उत्कृष्ट प्रतीक है।

प्रधानमंत्री को ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रदान की गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 6 जुलाई को ब्यूनस आयर्स शहर की सरकार के प्रमुख श्री जॉर्ज मैक्री ने ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रदान की। 'एक्स' पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, "ब्यूनस आयर्स

शहर की सरकार के प्रमुख श्री जॉर्ज मैक्री से ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 6-7 जुलाई को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा की, जिसमें वैश्विक शासन में सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को बुलंद करना, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, विकास के मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। श्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा को उनके गर्मजोशी से भरी मेहमाननवाजी और शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।

वैश्विक शासन में सुधार तथा शांति एवं सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने 'वैश्विक शासन में सुधार तथा शांति एवं सुरक्षा' विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। बाद में श्री मोदी ने 'बहुपक्षीय, आर्थिक-वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत बनाने' संबंधी विषय पर एक सत्र को भी संबोधित किया। इस सत्र में ब्रिक्स भागीदार और आमंत्रित देशों ने भाग लिया।

वैश्विक शासन और शांति एवं सुरक्षा पर सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के मामले में निरंतर विकास के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि 20वीं सदी के वैश्विक संगठनों में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का अभाव है, उन्होंने उनमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक शासन संस्थाओं को वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए तत्काल सुधार से गुजरना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने और शिखर सम्मेलन घोषणा-पत्र में इस मुद्दे पर एक मजबूत भाषा अपनाने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया।

आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा

शांति और सुरक्षा पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2025 में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। आतंकवाद के खिलाफ सख्त वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने वालों, उन्हें बढ़ावा देने या सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वालों से सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना

चाहिए। श्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का आह्वान करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस खतरे से निपटने में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए।

इस विषय पर विस्तार से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक संघर्ष गहरी चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा ऐसे संघर्षों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है और ऐसे प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है।

बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना

'बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मजबूत करना' विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता और बहुध्रुवीयता ब्रिक्स की महत्वपूर्ण ताकत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था दबाव में है और वैश्विक समुदाय अनिश्चितता और चुनौतियों का सामना कर रहा है, ब्रिक्स की प्रासंगिकता स्पष्ट है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस संबंध में उन्होंने चार सुझाव दिए:

- पहला, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए मांग आधारित सिद्धांत और दीर्घकालिक स्थिरता का पालन करना चाहिए।
- दूसरा, समूह एक विज्ञान और अनुसंधान भंडार स्थापित करने पर विचार करे, जो वैश्विक दक्षिण देशों को लाभान्वित कर सके।
- तीसरा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- चौथा, समूह को जिम्मेदार एआई के लिए काम करना चाहिए; एआई शासन की चिंताओं को देखते हुए इसे क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी समान महत्व देना चाहिए।

नेताओं के सत्र के समापन पर सदस्य देशों ने 'रियो डी जेनेरियो घोषणा' को स्वीकार कर लिया।

ब्राज़ील यात्रा

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 जुलाई को ब्राजील की राजकीय यात्रा की। यह यात्रा ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर की गई। मित्रता और विश्वास की भावना से हुई यह यात्रा लगभग आठ दशकों से ब्राजील-भारत संबंधों का आधार रही है।

नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों की विस्तृत श्रृंखला पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अपने संकल्प की पुष्टि की। साथ ही लोगों की शांति, समृद्धि और निरंतर विकास की खोज में योगदान देकर वैश्विक मामलों में अपने देशों की अलग-अलग भूमिकाओं को बरकरार रखते हुए साझा मूल्यों पर आधारित ऊंचे उद्देश्यों को आगे बढ़ाया।

विभिन्न समझौता ज्ञापन/समझौतों पर हस्ताक्षर

- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग पर समझौता।
- डिजिटल कायाकल्प के लिए सफल बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के आदान-प्रदान के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- ईएमबीआरएपीए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बीच कृषि अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन।
- गोपनीय सूचना के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौता।
- भारत के डीपीआईआईटी और ब्राजील के एमडीआईसी के प्रतिस्पर्धात्मकता और विनियामक नीति सचिवालय के बीच बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री मोदी 'द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' से सम्मानित

ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने 9

जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस विशिष्ट सम्मान के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति, सरकार और जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया।

इस पुरस्कार को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतवासियों और भारत और ब्राजील के बीच मित्रता के स्थायी संबंधों का सम्मान है। श्री मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति लूला भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी के निर्माता रहे हैं और यह पुरस्कार द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के उनके अथक प्रयासों के प्रति सम्मान है।

प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा

नामीबिया की राष्ट्रपति से मुलाकात: भारत-एसएसीयू पीटीए पर चर्चा में तेजी लाने का आह्वान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नामीबिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 9 जुलाई को राजधानी विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में नामीबिया की राष्ट्रपति महामहिम डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा से भेंट की। पिछले 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस संबंध में अब भी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना शेष है। इस संबंध में उन्होंने भारत-एसएसीयू पीटीए पर चर्चा में तेजी लाने का आह्वान किया।

एमओयू/समझौते

- ✦ नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना पर एमओयू
- ✦ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू

घोषणाएं

- ✦ नामीबिया ने सीडीआरआई (आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन) में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया
- ✦ नामीबिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया
- ✦ नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया

प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को किया संबोधित

नेशनल असेम्बली की स्पीकर महामहिम सारा कुगोंगेल्वा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जुलाई को नामीबिया की संसद को संबोधित किया। संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत हमेशा अफ्रीका की प्रगति के लिए काम करेगा, जैसाकि उसने जी-20 की अध्यक्षता के दौरान किया था, जब अफ्रीकी संघ को इस समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया था। श्री मोदी ने कहा कि भारत को नामीबिया और महाद्वीप के अन्य देशों के साथ अपने विकास के अनुभव साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित

नामीबिया की राष्ट्रपति महामहिम नेटुम्बो नंदी-नदैतवा ने 9 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सचिया मिराबिलिस' से सम्मानित किया। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं।

प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया जाना भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह दोनों देशों के युवाओं के लिए इस विशेष द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने हेतु प्रेरणा का स्रोत है। ■

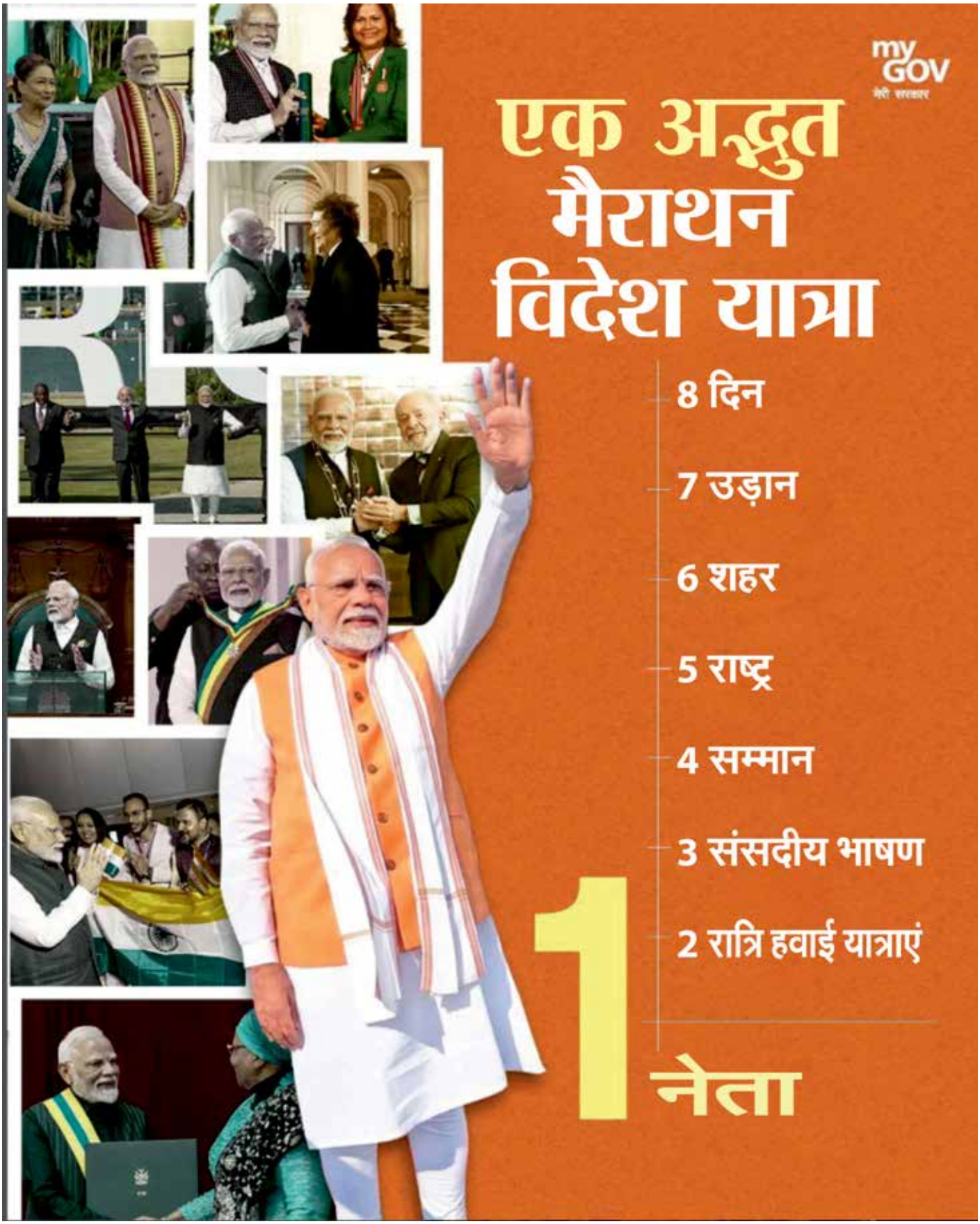
my GOV
मेरी सरकार
एक अद्भुत मैराथन विदेश यात्रा
8 दिन
7 उड़ान
6 शहर
5 राष्ट्र
4 सम्मान
3 संसदीय भाषण
2 रात्रि हवाई यात्राएं
1 नेता

दिल्ली एवं हरियाणा भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालयों का उद्घाटन

भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है कि यह विचार आधारित पार्टी है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 6 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली स्थित भाजपा केन्द्रीय कार्यालय विस्तार से दिल्ली एवं हरियाणा के नवनिर्मित तीन-तीन जिला भाजपा कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया और बीते 11 वर्षों में प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली, सांसद श्री मनोज तिवारी, सांसद श्री प्रवेश वर्मा, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज एवं अन्य वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि आज जब एक साथ छह स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का लोकार्पण हो रहा है, तो यह कार्यक्रम और भी विशेष बन जाता है क्योंकि आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 124वीं जयंती भी है। भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष का बीज उन्हीं ने रोपा था। इसलिए आज का दिन उन्हें स्मरण करने का दिन है, यह केवल भाजपा कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसका एक भावनात्मक संबंध भी है।

उन्होंने कहा कि देश कभी भी डॉ. मुखर्जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि आज बंगाल और उत्तर-पूर्व भारत हमारे साथ है, तो उसका श्रेय डॉ. मुखर्जी के संसद में दिए गए सशक्त हस्तक्षेप को जाता है। उन्होंने नेहरू सरकार के तुष्टीकरण के विरुद्ध आवाज उठाई और पहली केंद्रीय मंत्रिपरिषद् से इस्तीफा देकर वैचारिक संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना कर एक वैकल्पिक विचारधारा की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में फलीभूत हो चुकी है। श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के धारा 370 के विरुद्ध संघर्ष और रहस्यमय परिस्थितियों में हुए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 11 मई, 1953 को उनकी गिरफ्तारी हुई और 23 जून को श्रीनगर की जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज उन्हें स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि देने का नहीं, बल्कि उनके जीवन चरित्र से मार्गदर्शन लेने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोकसभा में दिए गए ऐतिहासिक भाषणों और पंडित नेहरू को लिखी गई चिट्ठियों को अवश्य पढ़ें। उनमें देश के प्रति अग्निसमान समर्पण की भावना स्पष्ट झलकती है। उन्होंने नेहरू जैसे नेता को भी बेबाकी से सच सुनाने का साहस दिखाया था।

उन्होंने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई, जिनके अथक प्रयासों से दिल्ली में तीन और हरियाणा में तीन नए कार्यालयों की स्थापना संभव हुई। दिल्ली में कार्यकर्ताओं

ने सरकार बनाई और हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा। 9 जून, 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 वर्ष पूर्ण किए। ये 11 वर्ष केवल एक कार्यकाल नहीं, बल्कि जनसेवा, साधना और समर्पण की वह यात्रा रही है, जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। इस कालखंड ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट होता है, संकल्प अडिग होता है और नीयत जनसेवा की होती है, तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृढ़ नेतृत्व ने इन 11 वर्षों को सिद्धियों की गाथा में परिवर्तित कर दिया है। 'सेवा' भारतीय जनता पार्टी का केवल नारा नहीं, बल्कि कार्य करने की मूल संस्कृति है। जब कोरोना काल में देश के बड़े-बड़े राजनीतिक दल या तो क्वारंटीन में चले गए या राजनीतिक तौर पर 'आईसीयू' में चले गए, उस कठिन समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही 'सेवा ही संगठन' के मंत्र को जीवन में उतारते हुए करोड़ों लोगों की सेवा की और देश के साथ खड़े रहे। सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 'न्यू नॉर्मल' स्थापित हुआ है। जब उरी की घटना हुई, तब उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई और हाल की पहलगाम की आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर कई स्थानों पर उनके सैन्य केंद्रों को ध्वस्त किया गया। इन सैन्य कार्रवाइयों ने देश को यह विश्वास दिया है कि भारत अब अपने दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर जवाब देने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का ही परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें पर आ चुकी है और चौथे स्थान की ओर अग्रसर है। यह बदलाव भारतीयता जनता पार्टी की नीतियों की स्पष्टता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है।

श्री नड्डा ने कहा कि आज जिन छह स्थानों, दिल्ली के महरौली, नजफगढ़, बाहरी दिल्ली तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर में कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है, वह इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थित संगठनात्मक ढांचे के साथ कार्य कर रही है। इन कार्यालयों को आईटी सेक्शन, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीडिया इंटरैक्शन एरिया, रिसर्च सेंटर, और रणनीति निर्माण की सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इस विचार की उत्पत्ति 2014 में हुई, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर जिले में पार्टी कार्यालय की कल्पना प्रस्तुत की। इसके पश्चात् श्री अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा ने 772 कार्यालयों के निर्माण का लक्ष्य तय किया। आज यह बताते हुए मुझे खुशी है कि 582 कार्यालय पूरे हो चुके हैं और लगभग 150 कार्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय सिर्फ ऑफिस नहीं हैं। ऑफिस सुबह 9 से 5 तक चलता है, लेकिन पार्टी का कार्यालय 24 घंटे चलता है। ये विचार, संगठन और संस्कारों के केंद्र हैं। यहां से नीति निर्धारण होता है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, रणनीति बनती है और जन संवाद का माध्यम बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कि यह विचार आधारित पार्टी है। भाजपा कार्यकर्ता सत्ता के लिए दिशा नहीं बदलते। 1953 में डॉ. मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं हो सकते। 2019 में श्री नरेन्द्र मोदी की इच्छाशक्ति और श्री अमित शाह की रणनीति से धारा 370 समाप्त हुई। यह केवल राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक लड़ाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। 1989 में पालमपुर में भाजपा ने प्रस्ताव पारित किया था कि हम राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वर्षों की लोकतांत्रिक लड़ाई के बाद, 2024 में भव्य राम मंदिर बना और देश ने एक ऐतिहासिक पल देखा।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना आर्थिक मॉडल है— पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 'एकात्म मानववाद'। इस दर्शन को भाजपा ने 'अंत्योदय' से जोड़कर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की दिशा में बढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण के चार प्रमुख स्तंभों को 'ज्ञान, ग़रीब, युवाशक्ति, अन्नदाता और नारीशक्ति' से जोड़ा। इन चारों वर्गों को सशक्त बनाकर ही 'विकसित भारत' के संकल्प की दिशा में ठोस कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल विचारधारा आधारित ही नहीं बल्कि कैडर आधारित पार्टी हैं, जिसकी देशभर में 973 जिला कमेटियां, 15,432 ब्लॉक यूनिट्स, 1,16,000 शक्ति केंद्र और 6,80,000 बूथ अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हैं, जिसका दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं जिन्हें विश्व के 25 देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज देश में 13 बीजेपी शासित सरकारें और 6 एनडीए सरकारें मिलाकर 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। देश में भाजपा के 240 लोकसभा सांसद, 98 राज्यसभा सदस्य, 1664 विधायक, 172 एमएलसी, 77 मेयर और हजारों जिला परिषद् व बीडीसी सदस्य हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है।

भाजपा कार्यालय सिर्फ ऑफिस नहीं हैं। ऑफिस सुबह 9 से 5 तक चलता है, लेकिन पार्टी का कार्यालय 24 घंटे चलता है। ये विचार, संगठन और संस्कारों के केंद्र हैं

श्री नड्डा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो हम सभी ने अनुभव किया है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान का आशीर्वाद बना रहे और भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। ■

राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक है : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 जून, 2025 को तेलंगाना के निजामाबाद में किसान महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इससे पहले श्री शाह ने निजामाबाद के लोकप्रिय नेता डी. श्रीनिवासजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2023 में हल्दी बोर्ड की स्थापना का जो वादा किया था, उसे न सिर्फ पूरा किया है बल्कि इंदूर की धरती पर हल्दी बोर्ड का मुख्यालय देकर हल्दी किसानों की चार दशक पुरानी मांग पूरी की है। उन्होंने कहा कि मोदीजी जो वायदा करते हैं, उसे पूरा करते हैं।

उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड को चालू करने से अब निजामाबाद की हल्दी विश्व के बाजार में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हल्दी के दाम कई बार गिर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हल्दी के दाम कभी नहीं गिरेंगे। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड हल्दी के औषधीय विशेषताओं को देश-दुनिया में प्रस्थापित करेगा। निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केन्द्र बनेगा। किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और किसानों को ताकत मिलेगी।

तेलंगाना में पिछली बीआरएस की सरकार ने धारामी, कालेश्वरम प्रोजेक्ट और टीएसपीएससी भर्ती सहित हर योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने दो कोऑपरेटिव्स बनाए हैं– भारत एक्सपर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड और भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड। इन दोनों कोऑपरेटिव्स की शाखाएं निजामाबाद में खोलने का निर्णय कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए बहुत जल्द ही एक पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी और ऑर्गेनिक हल्दी उत्पादक किसानों के उत्पादों को अमेरिका, यूरोपियन संघ, कनाडा, यूके, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि एक जमाना था जब दस साल तक विपक्ष की सरकार थी। उस वक्त आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हमले करते थे और भाग जाते थे। कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार में दस साल में तीन बार हमले के बड़े प्रयास किए गए। पहले उरी, फिर पुलवामा और फिर पहलगाम। उरी में हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला किया तो हमने एयर स्ट्राइक की और पहलगाम में हमला किया तो पाकिस्तान में घुस कर मारा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि कई आदिवासी पैर, हाथ और जान गंवा बैठे। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि इन नक्सलियों को शरण में लाया जाए तो इसके लिए मना किसने किया है। नक्सलियों ने अगर सरेंडर नहीं किया तो हमने तय किया है कि 31 मार्च, 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस इन नक्सलियों से बातचीत करने के लिए कहती है। नक्सली हथियार डाल दें और मुख्यधारा में आ जाएं। 2 हजार से अधिक नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है लेकिन जिनके हाथ में हथियार है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि विपक्षी पार्टी देशभर से भागे हुए नक्सलियों को कहीं तेलंगाना में पनाह न दे दे। लेकिन आप चिंता मत करना, केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार है।

श्री शाह ने कहा कि तेलंगाना में पिछली बीआरएस की सरकार ने धारामी, कालेश्वरम प्रोजेक्ट और टीएसपीएससी भर्ती सहित हर योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया। विडंबना यह है कि अब सरकार में आने वाले रेवंत रेड्डी ने एक भी मामले में केस दर्ज नहीं किया है। तेलंगाना चंद्रशेखर राव के परिवार का एटीएम था, अब यह दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं का एटीएम बन गया है। तेलंगाना में आज भी भष्ट्राचार पिछली सरकार की तरह ही हो रहा है। आज भी नक्सलियों को बचाने की बात हो रही है। आज भी केन्द्र की योजनाओं को नीचे लागू नहीं होने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर यहां के लोग किसानों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं का भला चाहते हैं, तो उनका भला केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'डबल इंजन' सरकार ही कर सकती है। तेलंगाना के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक है। ■

'भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना समय 'विकसित केरलम्' के लिए समर्पित करना है'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 12 जुलाई, 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा केरल प्रदेश के कार्यालय का उद्घाटन किया और 'विकसित केरलम् सम्मेलन' को संबोधित किया। श्री शाह ने बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को 'विकसित केरलम्' व 'विकसित भारत' की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा केरल प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजीव चंद्रशेखर, केन्द्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, भाजपा केरल प्रदेश प्रभारी श्री प्रकाश जावड़ेकर, सह-प्रभारी श्रीमती अपराजित सारंगी एवं अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने भाजपा के भव्य कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को याद किया, जिन्होंने अपनी जान देकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

उन्होंने कहा कि कार्यालय का उद्घाटन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष क्षण है, क्योंकि भारतीय जनसंघ के समय से लेकर आज तक की इस यात्रा में ऐसे कई पड़ाव आए हैं जो संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि यह कार्यालय केवल संगठन का केंद्र न बनकर, केरल में एनडीए की सरकार बनाने की दिशा में एक सशक्त शुरुआत होगी। अन्य राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय मात्र एक काम करने की जगह होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय एक पवित्र स्थल होता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह मंदिर के समान होता है। कार्यालय के बिना पार्टी की विचारधारा कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच सकती और विचारधारा के बिना भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाजपा कार्यकर्ता दिन-रात कार्यालय में पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित रहते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय केवल एक संरचना नहीं, बल्कि संगठनात्मक चेतना का प्रतीक है। भाजपा की मान्यता है कि जिस प्रकार संगठन के मूलभूत विचार जनता से जुड़े हैं, उसी प्रकार कार्यालय भी जनता और कार्यकर्ता के बीच एक सशक्त सेतु बनकर कार्य करता है।

> **अन्य राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय मात्र एक काम करने की जगह होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय एक पवित्र स्थल होता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह मंदिर के समान होता है**

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत' की संकल्पना देश के 140 करोड़ नागरिकों के समक्ष रखी है और इस विकसित भारत का मार्ग, विकसित केरल से होकर ही जाता है। दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्यों के समग्र विकास के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। इस दिशा में यदि कोई राज्य सांस्कृतिक समन्वय,

प्राचीन विरासत और आधुनिकता का सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ सकता है, तो वह केवल और केवल महान केरल ही है। यह राज्य विविध संस्कृतियों का संगम है, जो विकास की धारणा को अपनी समृद्ध परंपराओं के साथ जोड़ते हुए एक नई दिशा में अग्रसर हो सकता है और यही वह ताकत है जो विकसित भारत की नींव को मजबूत बनाएगी। आज से भारतीय जनता पार्टी ने केरल में एक नए युग की शुरुआत की है। जिस आधार पर हम 'विकसित केरलम्' की परिकल्पना करते हैं, उसके मूल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीन प्रमुख सिद्धांत निहित हैं। पहला सिद्धांत है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था, दूसरा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। तीसरा सिद्धांत है कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के समग्र विकास की संकल्पना को साकार किया जाए।

उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों कैडर आधारित पार्टी है। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा फर्क है, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास से ऊपर है कैडर का विकास, वहीं भाजपा के लिए 'विकसित केरलम्' सबसे ऊपर है। केरल की जनता ने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को कई वर्षों तक मौका दिया, लेकिन इन दोनों ने सिर्फ हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया।

श्री शाह ने कहा कि 'विकसित केरलम्' के संकल्प को साकार करने के लिए जब-जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केरल की जनता के बीच पहुंचे, भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने केरल की जनता से आग्रह करते हुए कहा कि आगामी लोकल बॉडी चुनाव में भाजपा और एनडीए 21,000 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा का लक्ष्य 25 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करने का है। इसलिए आज से लेकर नवंबर तक का सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना समय 'विकसित केरलम्' के लिए समर्पित करना है। ■

'केंद्र सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जुलाई, 2025 को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और बादल फटने व भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का निरीक्षण किया। श्री नड्डा ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र स्थित सैंज पंगलियूर बागा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात की। उन्होंने थुनाग में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और लोगों से बात की, साथ ही उन्होंने करसोग और धर्मपुर में हुए नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। इस दौरान उनने साथ हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल भी मौजूद थे।

श्री नड्डा ने सबसे पहले मंडी जिला के सुंदरनगर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए और हर प्रभावित व्यक्ति तक सरकार की सहायता शीघ्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रही है और आवश्यक संसाधन समय पर मुहैया कराए जा रहे हैं। तत्पश्चात् उन्होंने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र स्थित सैंज पंगलियूर बागा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों से भेंट की। इस दौरान वह पुष्प राज और तिलक राज ने मिले जिन्होंने इस त्रासदी में अपने माता पिता को खो दिया।

श्री नड्डा ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनके पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उन्होंने मंडी जिले के ही थुनाग गांव का दौरा किया, जहां भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने वहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और राहत सामग्री वितरण की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, अस्थायी आश्रय देने और भोजन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया और इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राहत कार्यों के बाद जिन क्षेत्रों में संपर्क मार्ग टूट गए हैं, उनकी शीघ्र मरम्मत कर पुनः यातायात सुचारू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और ऐसे समय में सरकार और समाज को मिलकर एकजुटता दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि सामान्य जनजीवन जल्द बहाल हो सके।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब भी हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने वहां का दौरा किया है, लोगों से बात की है तथा केंद्र से इस आपदा से उबरने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।

मुख्य बिंदु

- केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है
- अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए और हर प्रभावित व्यक्ति तक सरकार की सहायता शीघ्र पहुंचे
- केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रही है
- आपदा त्रासदी में माता पिता को खोने वाले पुष्प राज और तिलक राज से भेंट कर सांत्वना दी
- फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, अस्थायी आश्रय देने और भोजन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है

अभिनंदन! अभिनंदन! अभिनंदन!

नए भाजपा प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा

श्री मनमोहन सामल
08 जुलाई, 2025 को पुनः ओडिशा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए

श्री महेश अगरिया
06 जुलाई, 2025 को दादरा और नगर हवेली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित हुए

श्री समिक भट्टाचार्य
03 जुलाई, 2025 को पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए

श्री हेमंत खंडेलवाल
02 जुलाई, 2025 को मध्यप्रदेश प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित हुए

श्री ताशी ग्यालसन काचू
02 जुलाई, 2025 को लद्दाख प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए

श्री रवींद्र चव्हाण
01 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित हुए

श्री एन. रामचंदर राव
01 जुलाई, 2025 को तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए

डॉ. राजीव बिंदल
01 जुलाई, 2025 को पुनः हिमाचल प्रदेश प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित हुए

श्री महेंद्र भट्ट
01 जुलाई, 2025 को पुनः उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए

श्री अनिल तिवारी
01 जुलाई, 2025 को अंडमान निकोबार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए

श्री पीवीएन माधव
01 जुलाई, 2025 को आंध्रप्रदेश प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित हुए

श्री वी.पी. रामलिंगम
30 जून, 2025 को पुडुचेरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए

डॉ. के. बेइचुआ
30 जून, 2025 को मिजोरम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित हुए

सभी नवनिर्वाचित प्रदेश भाजपा अध्यक्षों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी नेतृत्व द्वारा उन पर जताए गए विश्वास एवं भरोसे के लिए उनका आभार व्यक्त किया। 'कमल संदेश' परिवार भी सभी नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्षों को हार्दिक बधाई देता है। ■

भारत की आर्थिक प्रगति

भारत का कुल निर्यात 2024-25 में 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर को छू गया, जो 2023-24 में 778.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.01 प्रतिशत अधिक है। यह 2013-14 में 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तेज बढ़ोतरी को दर्शाता है

भारत की अर्थव्यवस्था स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ लगातार बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरकर सामने आ रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य का एक पैमाना है। यह किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। 2024-25 में वास्तविक जीडीपी बढ़ोतरी का अनुमान 6.5 प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि 2025-26 में भी यही दर जारी रहेगी। यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता का सामना कर रही है, जिससे भारत की स्थिर प्रगति और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

मजबूत घरेलू मांग, घटती मुद्रास्फीति, मजबूत पूंजी बाजार और बढ़ते निर्यात की मदद से देश की तस्वीर व्यापक आर्थिक लचीलेपन और संतुलन की है। रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार, प्रबंधनीय चालू खाता घाटा और बढ़ते विदेशी निवेश जैसे प्रमुख संकेतक, भारत की दीर्घकालिक संभावनाओं में बढ़ते वैश्विक भरोसे को दर्शाते हैं। साथ ही, ये रुझान एक ऐसी अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं जो न केवल फैल रही है बल्कि मजबूती के साथ सभी क्षेत्रों में ऐसा कर रही है।

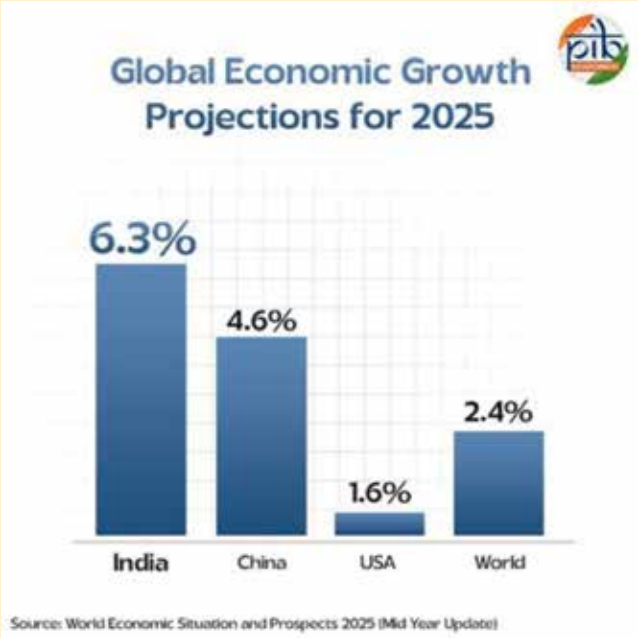

मजबूत जीडीपी बढ़ोतरी

भारत की प्रगति की कहानी पर पूरे विश्व का ध्यान जा रहा है, जिसे मजबूत बुनियादी बातों और लगातार प्रदर्शन का सहयोग मिला है। रियल जीडीपी, जिसे मुद्रास्फीति के असर को हटाने के बाद अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापा जाता है, 2024-25 में 6.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि यह गति 2025-26 तक जारी रहेगी। अन्य अनुमान इस आशावाद को दोहराते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने इस साल 6.3 प्रतिशत और अगले साल 6.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपना अनुमान थोड़ा अधिक 6.40 से 6.70 प्रतिशत रखा है।

इस अनवरत प्रदर्शन का आधार मजबूत घरेलू मांग है। ग्रामीण खपत में तेजी आई है, शहरी खर्च बढ़ रहा है और निजी निवेश में तेजी आ रही है। कारोबार फैल रहे हैं, जिनमें से कई अपने अधिकतम उत्पादन स्तर के करीब कार्यान्वयन कर रहे हैं। साथ ही, सार्वजनिक निवेश लगातार उच्च बना हुआ है, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि उधारी की स्थिर परिस्थितियों ने फर्मों और उपभोक्ताओं को भविष्य के प्रति फैसले लेने में मदद की है।

इसके ठीक उलट, वैश्विक परिस्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने व्यापार तनाव, नीतिगत अनिश्चितताओं और सीमा पार निवेश में गिरावट का हवाला देते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को 'अनिश्चितता के दौर' में बताया है। इसके बावजूद, भारत एक उज्ज्वल स्थान के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है, वैश्विक संस्थाओं और उद्योग निकायों ने इसकी प्रगति की संभावनाओं पर भरोसा जताया है।

बीते दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ा है। 2014-15 में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 106.57 लाख करोड़ रुपये थी। यह आंकड़ा 2024-25 में बढ़कर 331.03 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जो कि दस साल में लगभग तीन गुना उछाल है। बीते साल ही नॉमिनल जीडीपी में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि वास्तविक जीडीपी में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो अर्थव्यवस्था के अनवरत लचीलेपन और शक्ति को दर्शाता है।

नियंत्रण में मुद्रास्फीति

भारत में मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई है, जिससे घर और कारोबार, दोनों को राहत मिली है। मई, 2025 में सालाना आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति दर 2.82 प्रतिशत रही। यह फरवरी, 2019 के बाद का निम्नतम स्तर है। यह पिछले महीने से 34 बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट को भी दर्शाता है।

खाद्यान्नों की कीमतें, जो आमतौर पर कुल मुद्रास्फीति पर बड़ा असर डालती हैं, भी कम हुई हैं। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) ने मई, 2025 में केवल 0.99 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर दर्ज की। यह अक्टूबर, 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम खाद्य मुद्रास्फीति है। ग्रामीण और शहरी खाद्य मुद्रास्फीति क्रमशः 0.95 प्रतिशत और 0.96 प्रतिशत पर लगभग समान थी। अप्रैल, 2025 के मुकाबले खाद्य मुद्रास्फीति में 79 बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट आई, जो सब्जियों और अनाज जैसी जरूरी वस्तुओं में स्पष्ट गिरावट का रुझान दिखाती है।

जून, 2025 में जारी की गई भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति का आउटलुक अनुकूल बना हुआ है। फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते खाद्य कीमतों के स्थिर रहने की उम्मीद है। वैश्विक मोर्चे पर आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम फिलहाल कम दिखाई देता है। वैश्विक मांग में मंदी के कारण कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रहने की संभावना है। हालांकि, मध्य पूर्व में हाल के तनावों ने इस तस्वीर में कुछ अनिश्चितता जोड़ दी है।

कुल मिलाकर, रिजर्व बैंक का मानना है कि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप रहेगी। असल में, आने वाले महीनों में यह इस स्तर से थोड़ा नीचे भी गिर सकती है। सहजता का यह रुझान भरोसा दिलाता है कि कीमतों में मौजूदा स्थिरता अस्थायी नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिरता के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है।

बाजार का भरोसा उच्चतम स्तर पर

भारत के पूंजीगत बाजार तेजी से बढ़ रहे हैं और यह भरोसा साफ दिखाई दे रहा है। घरेलू बचत को निवेश में बदलकर वे आर्थिक प्रगति के लिए एक शक्तिशाली इंजन बन गए हैं। वैश्विक तनाव और घरेलू अनिश्चितताओं के बीच शेयर बाजार ने दिसंबर, 2024 तक मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा। इसने कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे पता चलता है कि स्थानीय और वैश्विक दोनों तरह के निवेशक भारत के विकास की कहानी पर कितना भरोसा करते हैं।

खुदरा भागीदारी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। खुदरा निवेशकों की संख्या 2019 में 4.9 करोड़ से बढ़कर 2024 के अंत तक 13.2 करोड़ हो गई। यह बढ़ोतरी इक्विटी बाजारों में बढ़ती सार्वजनिक रुचि और देश की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास को दर्शाती है। अब अधिकतर लोग शेयर बाजार को केवल बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी संपत्ति बनाने के एक जरिए के तौर पर देखते हैं।

प्राथमिक बाजार, जहां कंपनियां जनता को शेयर बेचकर धन जुटाती हैं, भी बहुत सक्रिय रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच भारत में 259 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आईपीओ आए। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले यह 32.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इन आईपीओ के जरिए जुटाई गई कुल राशि लगभग तीन गुना बढ़ गई, जो 53,023 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,53,987 करोड़ रुपये हो गई। वैश्विक आईपीओ लिस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी 2023 में 17 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 30 प्रतिशत हो गई, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

बाहरी क्षेत्र को मजबूत बनाना

भारत का बाहरी क्षेत्र अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा प्रदान करता रहता है। बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार, प्रबंधनीय चालू खाता बैलेंस और विदेशी निवेश के स्थिर इनफ्लो के साथ भारत वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है। ये संकेतक देश की आर्थिक नीतियों और दीर्घकालिक स्थिरता में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय भरोसे को दर्शाते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत वैश्विक निवेशकों के लिए शीर्ष विकल्प बना हुआ है। देश में निवेशक-अनुकूल एफडीआई नीति है, जो स्वचालित मार्ग के जरिए अधिकांश क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की अनुमति देती है। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई प्रवाह बढ़कर 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर (प्रोविजनल) हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में मिले 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दोगुने से भी अधिक है, जो दीर्घकालिक प्रगति को दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र ने इक्विटी निवेश के इनफ्लो का नेतृत्व किया, जिसने वित्त वर्ष 2024-25 में कुल एफडीआई का 19 प्रतिशत अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का स्थान रहा, जिसमें 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और 8 प्रतिशत पर लेन-देन हुआ। सेवा क्षेत्र में एफडीआई 40.77 प्रतिशत बढ़कर 9.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह 6.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एफडीआई में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 16.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

विदेशी मुद्रा भंडार

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20 जून, 2025 तक 697.9

बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये भंडार 11 महीने से अधिक के माल आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जो वैश्विक झटकों के समय सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही निर्यात धीमा हो जाए, लेकिन भारत के पास जरूरी आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। साथ ही, बाहरी कर्ज मध्यम स्तर पर बना हुआ है, जो मार्च, 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 19.1 प्रतिशत है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ भारत की वित्तीय स्थिति स्वस्थ और स्थिर है।

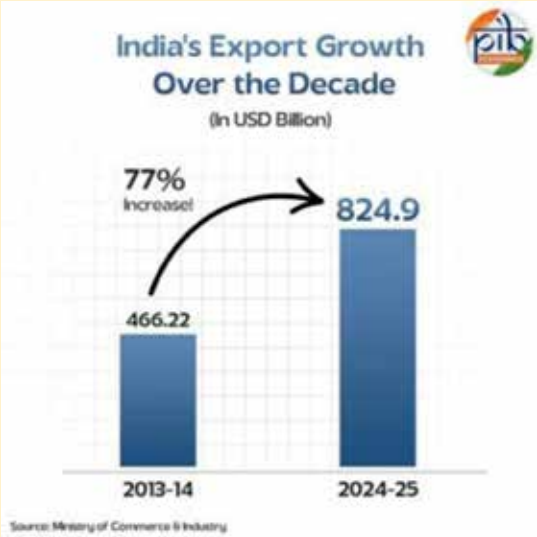

चालू खाता गतिकी

भारत के चालू खाता बैलेंस में 2024-25 की चौथी तिमाही में 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का सरप्लस दर्ज किया गया, जबकि बीते साल की इसी तिमाही में यह 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) था। यह सुधार भारत की निर्यात में आय की बढ़ती ताकत और विदेशी इनफ्लो की स्थिरता को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में चालू खाता घाटा जीडीपी के केवल 0.6 प्रतिशत पर सीमित रहा। घाटे में यह कमी मुख्य रूप से मजबूत सेवा निर्यात और विदेशों में रहने वाले भारतीयों से लगातार आने वाले धन के कारण हुई।

विनिर्माण और निर्यात

भारत का निर्यात प्रदर्शन इसकी अर्थव्यवस्था की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है, मुख्य रूप से सेवाओं और उच्च मूल्य वाले विनिर्माण में। बीते एक दशक में देश ने वैश्विक व्यापार में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। यह बढ़ोतरी मजबूत औद्योगिक क्षमता, सेवाओं में अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता और रक्षा उत्पादन व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में उभार से प्रेरित है।

भारत का कुल निर्यात 2024-25 में 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर को छू गया, जो 2023-24 में 778.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.01 प्रतिशत अधिक है। यह 2013-14 में 466.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तेज बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो एक दशक की निरंतर निर्यात गति को रेखांकित करता है।

सेवाओं का निर्यात एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है। 2024-25 में भारत ने 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सेवाएं निर्यात कीं, जो बीते साल के 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13.6 प्रतिशत अधिक है। एक दशक पहले 2013-14 में सेवाओं का निर्यात 152 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह मजबूत और निरंतर बढ़ोतरी वैश्विक ग्राहकों (मुख्य रूप से आईटी, कंसल्टिंग, वित्त और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में) को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देने की भारत की क्षमता को रेखांकित करती है।

पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर मर्चेंडाइज निर्यात ने भी रिकॉर्ड बनाया है। 2024-25 में ये निर्यात 374.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो बीते वर्ष के 352.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.0 प्रतिशत अधिक है। यह अब तक का सर्वाधिक गैर-पेट्रोलियम मर्चेंडाइज निर्यात आंकड़ा है। यह 2013-14 में 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी शानदार सुधार दर्शाता है। इस बढ़ोतरी का अधिकतर हिस्सा मशीनरी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरण जैसे क्षेत्रों से आया है, जो वैश्विक बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

निर्यात में इस बढ़ोतरी के पीछे विनिर्माण में लगातार बढ़ोतरी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2013-14 में 15.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 27.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 17.3 प्रतिशत पर स्थिर रही, लेकिन उत्पादन में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी इसके बढ़ते आधार को दर्शाती है।

निष्कर्ष

बीते एक साल में भारत का आर्थिक प्रदर्शन केवल प्रगति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि स्थिरता और दिशा की गहरी समझ को भी दर्शाता है। वास्तविक जीडीपी में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति के वर्षों के निम्नतम स्तर पर आने के साथ देश ने दिखाया है कि वह मूल्य स्थिरता के साथ विस्तार को संतुलित कर सकता है। साथ ही, पूंजीगत बाजारों में मजबूत भागीदारी, निर्यात के उच्चम स्तर और स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार घरेलू और विदेशी, दोनों ही स्तर पर बढ़ते भरोसे की ओर इशारा करते हैं।

विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्र, लगातार निवेश और नीतिगत फोकस की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। बाहरी जोखिम बने हुए हैं, लेकिन भारत की आधारभूत बातें मजबूत हैं। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना करना जारी रखती है, भारत का लगातार प्रदर्शन यह भरोसा देता है कि वह आगे बढ़कर नेतृत्व करने और एक सुदृढ़, अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ■

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को दी मंजूरी

एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को समर्थन देने की योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई को विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत जहां पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही, विनिर्माण क्षेत्र के लिए दो साल के लिए विस्तारित लाभ दिया जाएगा। ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये है।

ईएलआई योजना का लक्ष्य 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। इस योजना का लाभ 01 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। ■

कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई को राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्वीकृति दे दी। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह एक ऐतिहासिक पहल है।

नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी।

एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। यह खेल नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। ■

मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण (आरडीआई) योजना को दी मंजूरी

भारत के अनुसंधान और नवोन्मेषण इको-सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक रूपांतरणकारी कदम के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई को एक लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवोन्मेषण (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

गणेश प्रसाद

श्री गणेश प्रसाद बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक थे। आपातकाल के दौरान उन्हें भारत रक्षा नियम (डीआईआर) के तहत गिरफ्तार किया गया और लगभग चार महीने तक जेल में रखा गया। वह बिहार के चंपारण क्षेत्र में गौरक्षा आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार रहे। ■

श्री गणेश प्रसाद

जन्म तिथि
19/04/1940

राज्य
बिहार

शहर
हनुमानगढ़ी, वार्ड नंबर 12, मोतिहारी

दायित्व
जिला कार्यकारिणी सदस्य

सक्रिय वर्ष
1958-2004

डिजिटल इंडिया का एक दशक

नरेन्द्र मोदी

दस साल पहले हमने बहुत दृढ़ विश्वास के साथ अज्ञात क्षेत्र में एक साहसिक यात्रा शुरू की।

जबकि दशकों तक भारतीयों की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की क्षमता पर संदेह किया जाता रहा, हमने इस अप्रोच को बदल दिया और भारतीयों की, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा किया।

जबकि दशकों तक यह सोचा जाता रहा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से संपन्न और वंचित के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी, हमने इस मानसिकता को बदल दिया और संपन्न एवं वंचित के बीच की खाई को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया।

जब इरादा सही हो, तो इनोवेशन, कम सशक्त लोगों को सशक्त बनाता है। जब अप्रोच, समावेशी होता है, तो टेक्नोलॉजी; हाशिये पर रहने वालों के जीवन में बदलाव लाती है।

इस विश्वास ने डिजिटल इंडिया की नींव रखीः पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने, समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने और सभी के लिए अवसर प्रदान करने का मिशन।

2014 में इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी और सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच दुर्लभ थी। कई लोगों को संदेह था कि क्या भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश वास्तव में डिजिटल हो सकता है।

आज, उस सवाल का जवाब न केवल डेटा और डैशबोर्ड में है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में भी है। हम कैसे गवर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं, लेन-देन करते हैं और कैसे निर्माण करते हैं, डिजिटल इंडिया हर जगह है।

डिजिटल खाई को पाटना

2014 में भारत में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। 42 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 11 गुना ज़्यादा है, अब सबसे दूरदराज के गांवों को भी जोड़ती है।

भारत में 5G की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज़ गति से हुई है, जहां सिर्फ़ दो साल में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों और गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक पहुंच गया है।

इंडिया स्टैक, जो हमारी डिजिटल रीढ़ है, ने यूपीआई जैसे प्लेटफ़ॉर्म को सक्षम किया है, जो अब सालाना 100+ बिलियन लेनदेन को संभालता है। सभी वास्तविक समय के डिजिटल लेनदेन में से लगभग आधे भारत में होते हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे नागरिकों को ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे बिचौलियों को हटाया गया है और 3.48 लाख करोड़ की लीकेज की बचत हुई है।

स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए हैं और 6.47 लाख गांवों की मैपिंग की है, जिससे भूमि से संबंधित अनिश्चितता के वर्षों का अंत हुआ है।

सभी के लिए अवसर का लोकतंत्रीकरण

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त बना रही है।

ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क) एक क्रांतिकारी प्लेटफ़ॉर्म है जो खरीदारों और विक्रेताओं के विशाल बाज़ार के साथ सहज कनेक्शन प्रदान करके अवसरों की एक नई खिड़की खोलता है।

जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) आम आदमी को सरकार के सभी अंगों को सामान और सेवाएं बेचने में सक्षम बनाता है। यह न केवल आम आदमी को एक विशाल बाज़ार के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि सरकार के लिए पैसे भी बचाता है।

को सुरक्षित और निर्बाध रूप से होस्ट करता है।

हमारे जी-20 प्रेसीडेंसी के माध्यम से, भारत ने ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी और 25 मिलियन डॉलर का सोशल इम्पैक्ट फंड लॉन्च किया, जिससे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम अपनाने में मदद मिली।

ओएनडीसी ने हाल ही में 200 मिलियन ट्रांज़ेक्शन को पार कर लिया है, जिसमें से आखिरी 100 मिलियन ट्रांज़ेक्शन सिर्फ़ छह महीनों में हुए हैं। बनारसी बुनकरों से लेकर नागालैंड के बांस कारीगरों तक, विक्रेता अब बिना किसी बिचौलिए या डिजिटल एकाधिकार के, पूरे देश में ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं

कल्पना कीजिए: आप मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के ज़रिए आपकी क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। आपको अपना लोन मिल जाता है और आप अपना उद्यम शुरू कर देते हैं। आप जेम पर रजिस्टर होते हैं, स्कूलों और अस्पतालों को सप्लाई करते हैं और फिर ओएनडीसी के ज़रिए आगे बढ़ते हैं।

ओएनडीसी ने हाल ही में 200 मिलियन ट्रांज़ेक्शन को पार कर लिया है, जिसमें से आखिरी 100 मिलियन ट्रांज़ेक्शन सिर्फ़ छह महीनों में हुए हैं। बनारसी बुनकरों से लेकर नागालैंड के बांस कारीगरों तक, विक्रेता अब बिना किसी बिचौलिए या डिजिटल एकाधिकार के, पूरे देश में ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं।

जेम ने 50 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपये जीएमवी को भी पार कर लिया है, जिसमें 1.8 लाख से अधिक महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई सहित 22 लाख विक्रेताओं ने 46,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे किए हैं।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत की ग्लोबल ऑफरिंग

आधार, कोविन, डिजीलॉकर और फास्टैग से लेकर पीएम-वाणी और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तक भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का अब वैश्विक स्तर पर अध्ययन और अपनाया जा रहा है।

कोविन ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सक्षम बनाया, 220 करोड़ QR-verifiable प्रमाणपत्र जारी किए। 54 करोड़ यूजर्स के साथ डिजीलॉकर 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों

स्टार्टअप पावर और आत्मनिर्भर भारत का संगम

भारत अब दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुमार है, जहां 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। लेकिन यह सिर्फ़ स्टार्टअप मूवमेंट से कहीं ज्यादा है, यह एक तकनीकी पुनर्जागरण है।

जब बात युवाओं में एआई स्किल पैठ और एआई प्रतिभा एकाग्रता की आती है तो भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

1.2 बिलियन डॉलर के इंडिया एआई मिशन के माध्यम से भारत ने 34,000 जीपीयू तक वैश्विक स्तर पर बेजोड़ कीमतों पर 1 डॉलर/जीपीयू प्रति घंटे से भी कम कीमत पर पहुंच को सक्षम किया है, जिससे भारत न केवल सबसे किफायती इंटरनेट अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि सबसे किफायती कंप्यूट डेस्टिनेशन भी बन गया है।

भारत ने मानवता-प्रथम एआई का समर्थन किया है। एआई पर नई दिल्ली घोषणा जिम्मेदारी के साथ इनोवेशन को बढ़ावा देती है। हम पूरे देश में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहे हैं।

आगे की राह

अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा। हम डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल नेतृत्व की ओर इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड (India-first से India-for-the-world) की ओर बढ़ रहे हैं।

डिजिटल इंडिया, केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, यह लोगों का आंदोलन बन गया है। यह एक 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय इनोवेशन भागीदार बनाने के लिए अहम है।

सभी इनोवेटर्स, उद्यमियों और सपने देखने वालों के लिए: दुनिया, अगली डिजिटल सफलता के लिए भारत की ओर देख रही है।

आइए, हम वह बनाएं, जो सशक्त करे।

आइए, हम वह हल करें, जो वास्तव में मायने रखता है।

आइए, हम ऐसी तकनीक से नेतृत्व करें जो जोड़ती है, सबको साथ लाती है और सबका उत्थान करती है। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

जब सरकार चिंता करती है, तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रगति करती हैं

जगत प्रकाश नड्डा

पिछले 11 वर्षों में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो राजनीतिक इच्छाशक्ति, बेहतर वित्त पोषण और सभी के लिए किफायती, सुलभ, समान एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हमारे प्रयास हर नागरिक की भलाई को प्राथमिकता देते हुए एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित है।

गौरतलब है कि 2014 में भारत को स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित मानव संसाधन, दवाओं एवं निदान की उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता में कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा था, लेकिन आज एक सक्रिय स्वास्थ्य प्रणाली और व्यापक देखभाल केंद्रित दृष्टिकोण के कारण महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) इस क्रांति की आधारशिला है, जो स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाता है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करता है, बीमारियों से लड़ने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देता है। 1.77 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवा को समुदायों के और करीब ला रहे हैं। वहीं ई-संजीवनी एवं टेलीमानस जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने विशेषज्ञ परामर्श को सुलभ बनाया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की मातृ मृत्यु अनुमान अंतर-एजेंसी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर में 86 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जो वैश्विक औसत गिरावट 48 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है। शिशु मृत्यु दर में 73 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक गिरावट 58 प्रतिशत है।

जैसे-जैसे गैर-संचारी रोगों का बोझ बढ़ रहा है, निवारक देखभाल पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मुख, स्तन और गर्भाशय के कैंसर की जांच की जा रही है। मई तक लगभग 28 करोड़ लोगों की उच्च रक्तचाप, 27 करोड़ से ज्यादा लोगों की मधुमेह और 27 करोड़ लोगों की मुख कैंसर की जांच की जा चुकी है।

> **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की मातृ मृत्यु अनुमान अंतर-एजेंसी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर में 86 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जो वैश्विक औसत गिरावट 48 प्रतिशत से लगभग दोगुनी है। शिशु मृत्यु दर में 73 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक गिरावट 58 प्रतिशत है**

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। 2014 से अब तक छह नए टीके शुरू किए गए हैं, जिनमें मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। हमने टीकाकरण सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए U-WIN पोर्टल बनाने हेतु नवीनतम तकनीक का सहारा लिया है, जिसमें 10.68 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है और मई 2025 तक 42.75 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।

भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया, 2015 में मातृ एवं नवजात शिशुओं में टिटनेस का उन्मूलन किया गया, और 2024 में ट्रेकोमा का उन्मूलन किया गया। 2015-2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आई। हम 2023 में कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य तक पहुंच गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी के मामलों में 17.7 प्रतिशत और मृत्यु दर में 21 प्रतिशत की कमी आई है। टीबी के 'अज्ञात' मामले 2015 के 15 लाख से घटकर 2024 में 1.2 लाख हो गए हैं।

स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में भी सुधार हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1.13 प्रतिशत से बढ़कर 1.84 प्रतिशत (2014-2022) हो गया है, जबकि आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गया है।

निःशुल्क औषधि एवं निदान सेवाओं ने सामर्थ्य और सुगम्यता में वृद्धि की है, जिसके अंतर्गत 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयोगशाला सेवाएं, 34 राज्यों में सीटी स्कैन और 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में टेली-रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम से 28 लाख से अधिक रोगियों को लाभ हुआ है, जिससे ओओपीई में 8,725 करोड़ रुपये की बचत हुई है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) जैसी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों ने

दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाई हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) 2021 में शुरू किया गया था। इसके तहत 18,802 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 602 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और 730 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनएचएम के तहत 5.23 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया है, जिनमें 1.18 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में भी सुधार हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिस्से के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1.13 प्रतिशत से बढ़कर 1.84 प्रतिशत (2014-2022) हो गया है, जबकि आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गया है

2018 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा अधिकारियों के बीच की खाई को पाटता है।

पिछले 11 वर्षों ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की नींव रखी है। देश सभी के लिए सुलभ, किफायती और समान स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं)

भाजयुमो ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 100 प्रतीकात्मक संसद सभाएं आयोजित की

आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने हमारे लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इसके तहत भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में 25 से 28 जून के दौरान देश भर में 100 प्रतीकात्मक संसद सभाओं का आयोजन किया गया।

इन सभाओं के माध्यम से आपातकाल के दौर की परिस्थितियों को पुनर्जीवित किया गया तथा बताया गया कि कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान मानवाधिकारों का क्रूर दमन किया, संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम दुरुपयोग किया, राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक गिरफ्तारी की तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का काम किया।

श्री तेजस्वी सूर्या ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित ऐसी ही एक सभा का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "आज के युवाओं को आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी की काली विरासत के बारे में जानना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि उस समय की सत्तावादी मानसिकता के कारण हमारे लोकतंत्र को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन सभाओं के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा आपातकाल के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा है और वर्तमान पीढ़ी को उस दौर में हुए अन्याय एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन से परिचित करवा रहा है।"

इन आयोजनों में छात्रों, युवा नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने 1975-77 की

घटनाओं को अपने उल्लेखनीय शोध के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया।

युवाओं को प्रेरित और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। उनमें से उल्लेखनीय हैं— डॉ. एस जयशंकर (नई दिल्ली), डॉ. जितेंद्र सिंह (जम्मू और कश्मीर), श्री बैजयंत 'जय' पांडा (ओडिशा), असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा (गुवाहाटी), त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा (अगरतला), झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी (रांची), श्री कैलाश विजयवर्गीय (मध्य प्रदेश) और श्री सुवेंदु अधिकारी (पश्चिम बंगाल)।

भाजयुमो की इस महत्वपूर्ण पहल ने न केवल आपातकाल के चलते हमसे बिछुड़े हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि लोकतंत्र को महत्व देने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक युवा भारतीय को जागरूक भी किया। ■

महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का उपयोग

अन्नपूर्णा देवी

सशक्तीकरण की शुरुआत 'पहुंच' सुनिश्चित करने के साथ होती है— अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच से होती है । बीते दशक में अधिक समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त भारत का निर्माण करने पर केंद्रित मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से इस पहुंच को नए सिरे से परिभाषित किया गया है और सभी के लिए सुलभ बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस परिवर्तन में सबसे अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन से निर्देशित मंत्रालय ने लाभ को अंतिम छोर तक त्वरित, पारदर्शी और कुशल तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी को व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया है।

हम अक्सर कहते हैं, 'सशक्त महिलाएं, सशक्त भारत।' और सशक्तीकरण की शुरुआत 'पहुंच' सुनिश्चित करने के साथ होती है— अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच से होनी चाहिए। आज, यह पहुंच तेज़ी से डिजिटल होती जा रही है।

जो कभी आकांक्षापूर्ण था, वह अब क्रियाशील बन चुका है– ऐसा सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, रियल-टाइम डेटा सिस्टम और उत्तरदायी शासन पर ज़ोर दिए जाने की बदौलत संभव हुआ है।

मंत्रालय ने देखरेख, संरक्षण और सशक्तीकरण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करते हुए पोषण, शिक्षा, कानूनी सुरक्षा और आवश्यक अधिकारों तक पहुंच को मजबूत किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं और बच्चे न केवल अधिक स्वस्थ, अधिक सुरक्षित जीवन जी सकें, बल्कि वे आत्मविश्वासी नेतृत्वकर्ता और अमृत काल के परिवर्तनकर्ता के रूप में भी उभर सकें।

जैसाकि प्रधानमंत्री ने बहुत सटीक रूप से कहा है, "मैं प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के साधन के रूप में तथा आशा और अवसर के बीच की दूरी को पाटने वाले उपकरण के रूप में देखता हूं।" इस लोकाचार ने मैनुअल प्रक्रियाओं से लेकर रियल-टाइम डैशबोर्ड तक, असंबद्ध योजनाओं से लेकर एकीकृत प्लेटफार्मों तक हमारे परिवर्तन का मार्गदर्शन किया है।

> सशक्तीकरण की शुरुआत 'पहुंच' सुनिश्चित करने के साथ होती है— अधिकारों, सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच से होनी चाहिए। आज, यह पहुंच तेज़ी से डिजिटल होती जा रही है

इस परिवर्तन की आधारशिला सक्षम आंगनवाड़ी पहल है। भारत भर में 2 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए निरुपित यह कार्यक्रम बाल्यावस्था देखरेख और विकास की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पोषण, स्वास्थ्य सेवा और पूर्व-विद्यालयी शिक्षा सेवाओं की ज्यादा प्रभावी प्रदायगी संभव बनाते हुए इन केंद्रों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइस और नए-नए लर्निंग टूल्स के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।

देश भर में 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पोषण ट्रैकर के साथ एकीकृत करने से रियल-टाइम डेटा एंट्री, कार्य निष्पादन की निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो पाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और व्यापक प्रशिक्षण से लैस करके, यह पहल अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करती है। यह 2014 से पहले मौजूद मैनुअल रिकॉर्ड-कीपिंग और डेटा ब्लाइंड स्पॉट से एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है।

एक दशक पहले आईसीडीएस प्रणाली असंबद्ध डेटा, विलंबित प्रतिक्रियाओं और रियल-टाइम ट्रैकिंग की कमी से दबी हुई थी। पोषण ट्रैकर ने पोषण सेवा प्रदायगी में सटीकता, दक्षता और जवाबदेही की शुरुआत कर इस परिदृश्य को बदल दिया है ।

10.14 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अब इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, छह साल से कम उम्र के बच्चे और किशोरियां शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म विकास की निगरानी और पूरक पोषण प्रदायगी पर रियल-टाइम अपडेट को सक्षम बनाते हुए समय पर हस्तक्षेप और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित करता है। डिजिटल रूप से सशक्त सामुदायिक केंद्रों के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों की नए सिरे से परिकल्पना कर शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए-पोषण ट्रैकर महत्वपूर्ण रूप से स्वस्थ भारत, सुपोषित भारत के राष्ट्रीय विजन को आगे बढ़ा रहा है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (2025) से सम्मानित यह मंच 'पोषण भी पढ़ाई भी' का भी समर्थन करता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करते हुए विकसित भारत के अमृत काल में समग्र देखभाल को बढ़ावा दे रहा है।

पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) में पारदर्शिता को और मजबूत करने तथा लीकेज कम करने के लिए एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया गया है। इस डिलिवरी तंत्र को सुरक्षित, सटीक और सम्मानजनक बनाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि पोषण सहायता केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले।

प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यह मंत्रालय पोषण से बढ़कर महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित कर रहा है। शी-बॉक्स पोर्टल हर महिला को, चाहे वह किसी भी रोजगार की स्थिति में हो या संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हो, पॉश अधिनियम के तहत उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए सिंगल-विंडो एक्सेस प्रदान करता है, जिससे ऑनलाइन निवारण और ट्रैकिंग संभव हो पाती है। इस बीच, मिशन शक्ति डैशबोर्ड एंड मोबाइल ऐप संकट से घिरी महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करता है, उन्हें निकटतम वन स्टॉप सेंटर से जोड़ता है, जो अब लगभग हर जिले में चालू है। ये कदम इस बात का उदाहरण हैं कि तकनीक का उपयोग न केवल दक्षता के लिए, बल्कि न्याय, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भी किया जा रहा है।

एक दशक पहले मातृत्व लाभ की निगरानी करना मुश्किल था और इसमें देरी होती थी। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की शुरूआत की है, जो मातृ कल्याण की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव है। पीएमएमवीवाई नियम, 2022 के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि मिलती है। मिशन शक्ति के तहत, अगर दूसरा बच्चा लड़की है, तो बेटियों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देते हुए लाभ की राशि 6,000 रुपये तक बढ़ जाती है। कागज रहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से वितरित शुरुआत से अब तक 4 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों तक 1,9000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंच चुकी है।

पीएमएमवीवाई— आधार-आधारित प्रमाणीकरण, मोबाइल-आधारित पंजीकरण, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर सहायता और रियल-टाइम डैशबोर्ड का लाभ उठाते हुए एक पूर्णतः डिजिटल कार्यक्रम है। एक समर्पित शिकायत निवारण मॉड्यूल तथा पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला नागरिकों से संबंधित पोर्टल है,जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

ये लक्षित प्रयास ठोस नतीजे दे रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24) हो गया है, जिसमें 12 अंकों का शुद्ध सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। मातृ मृत्यु दर 130 प्रति 1000 जन्म (2014-16) से घटकर 97 प्रति 1000 जन्म (2018-20) हो गई है, जो हमारी सरकार के पिछले एक दशक के निरंतर प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है।

प्रत्येक बच्चा पोषित, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण का हकदार है। हाल के वर्षों में डिजिटल परिवर्तन ने बाल संरक्षण और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत मंत्रालय ने केयरिंग्स पोर्टल (बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली) के माध्यम से गोद लेने के इकोसिस्टम को मजबूत किया है। यह डिजिटल इंटरफ़ेस एक अधिक पारदर्शी, सुलभ और कुशल गोद लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

डिजिटलीकरण ने बाल देखभाल संस्थानों, पालन-पोषण केंद्रों और जेजे अधिनियम के तहत वैधानिक सहायता संरचनाओं की निगरानी में भी सुधार किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म बाल अधिकारों के उल्लंघन पर सक्रिय रूप से नज़र रख रहे हैं। इस बीच मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड विभिन्न बाल कल्याण हितधारकों के बीच अभिसरण और समन्वय को मजबूत करता है।

यह नया भारत है— जहां शासन प्रौद्योगिकी से मिलता है और जहां नीति उद्देश्य से मिलती है। पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने न केवल डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है, बल्कि इसका समर्थन भी किया है।

जैसे-जैसे हम अमृत काल में आगे बढ़ रहे हैं, मंत्रालय प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे का राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनना सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व करना जारी रखेगा। प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और लक्षित कार्रवाई के माध्यम से, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां सशक्तीकरण महज नारा भर नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए वास्तविकता है। ■

(लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
राष्ट्रीय एकता के अखंड पुजारी

शिवप्रकाश

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को सर आशुतोष मुखर्जी एवं श्रीमती जोगमाया देवी के परिवार में कलकत्ता में हुआ था। डॉ. श्यामा प्रसाद अपने माता–पिता की सात संतानों में से दूसरी संतान थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर विद्वान थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने एवं कुलपति के दायित्व का दो बार निर्वहन किया।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अनेक मौलिक सुधार किए। उस समय हम अंग्रेजी दासता के अधीन थे। उन्होंने शिक्षा को स्वाभिमान के साथ जोड़ा। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक चिह्न को बदलकर पूर्ण खिलते कमल के मध्य 'श्री' लिखवाया। जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उस समय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह अंग्रेजी भाषा में होते थे। 1937 के दीक्षांत समारोह में उन्होंने गुरुवर रवींद्रनाथ ठाकुर को बुलाया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने नई परंपरा प्रारंभ करते हुए अपना भाषण बांग्ला भाषा में दिया। महिला शिक्षा में वृद्धि, भारतीय विद्वानों को अवसर, भारतीय संस्कृति का समावेश शिक्षा क्षेत्र में उनके द्वारा की गई पहल है।

1929 कलकत्ता विश्वविद्यालय चुनाव क्षेत्र से वह बंगाल विधान परिषद् में गए। बंगाल में मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी की गठबंधन सरकार द्वारा हिंदू समाज के उत्पीड़न के विरोध के लिए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। हिंदू समाज के संरक्षण का यह कार्य वह अपने मृत्युपर्यंत करते रहे। बाद में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से जुड़े एवं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने।

तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. सुहरावर्दी भाषा के नाम पर संयुक्त बंगाल का नारा दे रहे थे। उनकी योजना थी कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा एवं संपूर्ण बंगाल पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। अज्ञानतावश कुछ कांग्रेस नेता भी इसका समर्थन कर रहे थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस षड्यंत्र को समझा एवं उद्घोष किया, "न तो हम पाकिस्तान में रहेंगे, न संयुक्त बंगाल में। हम भारत का हिस्सा है और भारत के ही साथ रहेंगे।" इसके लिए उन्होंने तीव्र आन्दोलन खड़ा किया। कांग्रेस के नेताओं एवं लार्ड माउंटबेटन को पत्र एवं संवाद के द्वारा यह समझाने में सफलता प्राप्त की कि यदि पंजाब विभाजन संभव है तो बंगाल क्यों नहीं। आज हम गर्व के साथ यह अनुभव कर सकते हैं कि यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो बंगाल भारत में नहीं होता। इस संकट की अनुभूति हमको इससे और अधिक तब हो सकती है, जब हम आज बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं के साथ इसकी तुलना करे। जहां न तो हिंदू सुरक्षित है और न ही उनकी आराध्य मां काली और उनका मंदिर। बांग्लादेश को उसका राष्ट्रगीत देने वाले गुरुवर रवींद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा भी तोड़ी जा रही है। जो अपने पितृपुरुष बंगबंधु मुजीबुर रहमान को ही स्वीकार नहीं कर रहे, वह हिंदू समाज को कैसे करेंगे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी दूरदृष्टि से इसे पहचाना था। आज यदि बंगाल हमारे पास न होता तब भारत का उत्तर पूर्व का भाग भी हमारे साथ नहीं होता है। आज भारत को जोड़ने वाले चिकन नेक के सामरिक महत्व को हम सभी

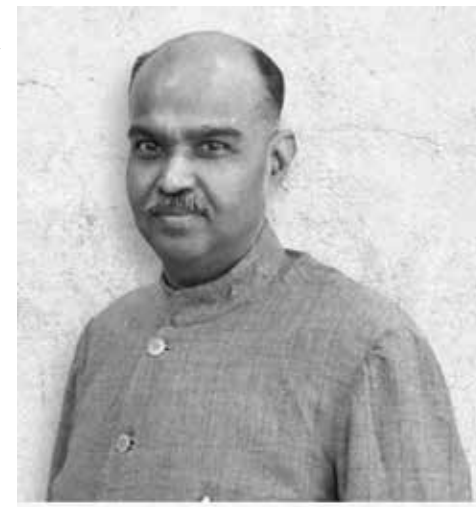

समझ रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से बंगाल की खाड़ी का महत्व कलकत्ता के साथ जोड़कर ही देखा जा सकता है। जिस खतरे का डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने अनुमान कर अपनी दूरदृष्टि से बंगाल को भारत के साथ रख कर दिया। आज वह संकट बंगाल में हम सभी के सम्मुख खड़ा दिखाई दे रहा है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रधानमंत्री नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री थे। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का मतान्तरण, अत्याचार एवं भारत में आए शरणार्थी हिंदुओं की उपेक्षा के कारण वह बहुत दुःखी थे। समस्या के समाधान के लिए नेहरू लियाकत समझौता भी पक्षपातपूर्ण होने के कारण उन्होंने हिंदुओं के प्रति नेहरू सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण अपना त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता आकर शरणार्थी हिंदू समाज की सेवा में जुड़ गए।

उद्योग मंत्री रहते हुए 1948 में भारतीय उद्योग नीति का निर्माण किया। औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करते हुए उन्होंने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया की भी 1948 में स्थापना की। आत्मनिर्भरता के मंत्र से युक्त औद्योगिक नीति उन्होंने दी। चार क्षेत्र-रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे एवं

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने ऐतिहासिक मिशन से पृथ्वी पर लौटने पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन शुक्ला की यह उपलब्धि देश की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक निर्णायक क्षण है।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं समस्त देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान' की दिशा में एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है।" ■

वायुसेवा उनके Focus क्षेत्र थे। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री (H.A.L.) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स प्लांट धनबाद, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध, भिलाई स्टील प्लांट उनके द्वारा स्थापित प्रसिद्ध उद्योग हैं। जो देश के विकास में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल राजनेता नहीं, समाज के प्रति संवेदनशील एवं सेवाभावी नेता थे। 1943 में बंगाल में भीषणतम अकाल आया। इस अकाल में लगभग 30 लाख लोगों के मरने का अनुमान था। यह अकाल केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, ब्रिटिश शासन की विफलताओं के कारण आया था। प्रशासन भी अन्न राहत देने के स्थान पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा था एवं सामान्य जनता को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया था। उन्होंने इस समय ब्रिटिश सरकार एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री की असफल नीतियों का प्रचंड विरोध किया। स्वयं समाज से सहायता सामग्री एकत्रित कर सेवा एवं राहत कार्यों का नेतृत्व किया। अकाल पीड़ितों की सेवा में इतने निमग्न हो गए थे कि अपनी पुत्री के विवाह के समय पिता द्वारा होने वाले रस्म 'संप्रदान' के समय भी उपस्थित नहीं रह पाए।

स्वतंत्रता के पश्चात् देश को राष्ट्रवादी नीतियों, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। स्थापना के समय उन्होंने कहा, "हमें कांग्रेस के राष्ट्रवादी विकल्प की जरूरत है।" प्रथम संसद में उन्होंने नेहरू जी के तानाशाहीपूर्ण मनोवृति का विरोध करने के लिए संयुक्त गठबंधन बनाया था। वह नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (N.D.P.) कहलाता था, जिसमें 34 सांसद लोकसभा एवं 20 सांसद राज्यसभा के थे तब नेहरू जी ने कहा था, "I will crush the Jan Sangh." (मैं जनसंघ को कुचल दूंगा।)" इस पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, "I will crush this crushing mentality" (मैं इस कुचलने वाली मानसिकता को ही कुचल दूंगा।) यह उनकी लोकतंत्र में आस्था एवं साहस का परिचायक है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाबोधि सोसाइटी के 1942 से 1953 तक अध्यक्ष रहे। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 1952 में सारिपुत्र एवं महामोगलन की अस्थियों के पवित्र भाग को सांची में स्थापित कराने वाले वह प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए म्यांमार (बर्मा), वियतनाम और थाईलैंड की यात्रा की। धारा 370 की समाप्ति एवं एक देश के अंदर 'दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे' का उद्घोष करने वाले राष्ट्रीय एकता के वे अखंड पुजारी थे। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए 23 जून, 1953 को अपना बलिदान देकर वह हमारे मध्य से चले गए। आज राष्ट्र उनके संकल्प की पूर्ति कर उनके जन्म दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 'मन की बात' को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना

'विकसित भारत निर्माण' के लिए मार्गदर्शित करनेवाला संवाद

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जून, 2025 को हरियाणा के जीएनएच कन्वेंशन हॉल, सोहना (गुरुग्राम) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जनप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 123वें एपिसोड को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर श्री नड्डा के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली, हरियाणा से भाजपा सांसद श्रीमती सुधा यादव समेत भाजपा के कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना। 'मन की बात' कार्यक्रम सुनने के बाद श्री नड्डा ने 70 वर्ष से उपर वाले वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य कवरेज हेतु आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए।

श्री नड्डा ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दुनियाभर में नागरिकों के योग के प्रति उत्साह, देश में संचालित विभिन्न ऐतिहासिक एवं धार्मिक यात्राओं के पौराणिक महत्व के साथ ही आपातकाल के 50 वर्ष में संविधान हत्या दिवस का जिक्र करते हुए लोकतंत्र सेनानियों का स्मरण किया और मेघालय व बोडोलैंड में लोगों द्वारा किये जा रहे नवाचार को लेकर प्रेरणास्पद विचार साझा किये।

श्री नड्डा ने जन-जन को एक सूत्र में पिरोने और 'विकसित भारत निर्माण' के लिए मार्गदर्शित करने वाले इस संवाद हेतु प्रधानमंत्रीजी का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज 'मन की बात' कार्यक्रम में भारत के ट्रेकोमा मुक्त होने की बात कही। उन्होंने इसे भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य शक्ति एवं सामूहित योगदान का प्रमाण बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, यह एक ऐसी बीमारी के उन्मूलन का प्रतीक है, जो कभी व्यापक अंधेपन का कारण बनती थी। भारत के लिए यह एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों, योजनाओं और कार्यान्वयन के कारण आज भारत एक स्वस्थ, रोग-मुक्त भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि घर पर छोटे-छोटे और सचेत विकल्पों से स्वस्थ भारत का निर्माण शुरू होता है। प्रधानमंत्रीजी ने सभी नागरिकों से '10 प्रतिशत कम तेल चुनौती' में भाग लेने की अपील की है, अर्थात् खाना पकाने के तेल की खपत में 10 प्रतिशत की कमी करने का आह्वान किया है, ताकि देशवासी मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों से बच सके। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं सहित देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाएं और इसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक सच्चे जन आंदोलन में बदल दें।

- भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जनप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के 123वें एपिसोड को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना
- श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज 70 वर्ष से उपर वाले वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य कवरेज हेतु आयुष्मान कार्ड वितरित किए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लोकप्रिय 'मन की बात' कार्यक्रम देश के हर हिस्से और सूदूर गांवों में भी सुना जाता है। यह रेडियो कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्राडकॉस्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल है। 'मन की बात' कार्यक्रम को आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्राडकास्टिंग सेंटर से ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार 'मन की बात' कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचें ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला से हुई बातचीत की भी चर्चा की। साथ ही, प्रधानमंत्रीजी ने स्थानीय सामान खरीदने और बेचने की अपील की और योग दिवस पर योग करते हुए देशभर से आई भव्य तस्वीरों की भी चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री, हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कथनों को अपने जीवन में उतारते हुए इस कार्यक्रम की प्रेरणादायी कहानियों को घर-घर पहुंचाने की अपील की। हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली ने कहा कि हमें प्रधानमंत्रीजी के कथनानुसार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षजी के नेतृत्व में देश और समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहना चाहिए। ■

आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी-न-किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं: नरेन्द्र मोदी

भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जून को मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 123वीं कड़ी के प्रारंभ में कहा कि आप सब इस समय योग की ऊर्जा और 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की स्मृतियों से भरे होंगे। इस बार भी 21 जून को देश-दुनिया के करोड़ों लोगों ने 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' में हिस्सा लिया। आपको याद है, 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ। अब 10 साल में ये सिलसिला हर साल पहले से भी ज्यादा भव्य बनता जा रहा है। ये इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दैनिक जीवन में योग को अपना रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हमने इस बार 'योग दिवस' की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर तीन लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया, दो हजार से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए, कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में तीन हजार दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तीकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू-कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और ITBP के जवान, वहां भी योग दिखा, साहस और साधना साथ-साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 (इक्कीस सौ इक्कीस) लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया।

उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आईं और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, 'Yoga for One Earth, One Health, यानी, 'एक पृथ्वी — एक स्वास्थ्य'। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक दिशा है जो हमें 'वसुधैव कुटुंबकम्' का अहसास कराती है। मुझे विश्वास है, इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ

श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। कैलाश मानसरोवर यानी भगवान शिव का धाम। हिन्दू, बौद्ध, जैन, हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो, या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' के भाव का प्रतिबिंब है।

श्री मोदी ने कहा कि जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा सम्पन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मैं यात्राओं पर जा रहे सभी सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग सेवा भावना से इन यात्राओं को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं।

ट्रेकोमा मुक्त भारत

श्री मोदी ने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' यानी WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रेकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है, जिन्होंने बिना थके, बिना रुके, इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे स्वास्थ्यकर्मियों की है। 'स्वच्छ भारत अभियान' से भी इसे मिटाने में बड़ी मदद मिली। 'जल जीवन मिशन' का भी इस सफलता में बड़ा योगदान रहा। आज जब घर-घर नल से साफ पानी पहुंच रहा है, तो ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो गया है। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' WHO ने भी इस बात की सराहना की है कि भारत ने बीमारी से निपटने के साथ-साथ उसके

मूल कारणों को भी दूर किया है।

उन्होंने कहा कि आज भारत में ज्यादातर आबादी किसी-न-किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ का फायदा उठा रही है और अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन – ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई-न-कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा - ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी-न-किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा, हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा।

आपातकाल लगाने वालों ने हमारे संविधान की हत्या की

श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडीज साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। 'मीसा' (MISA) के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। छात्रों को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया।

उन्होंने कहा कि उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है, वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार, जनता-जनार्दन की जीत हुई– आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए।

श्री मोदी ने कहा कि देश पर आपातकाल थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने 'संविधान हत्या दिवस' मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए, जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

रियो डी जेनेरियो (ब्राजील) में 07 जुलाई, 2025 को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक समूहचित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

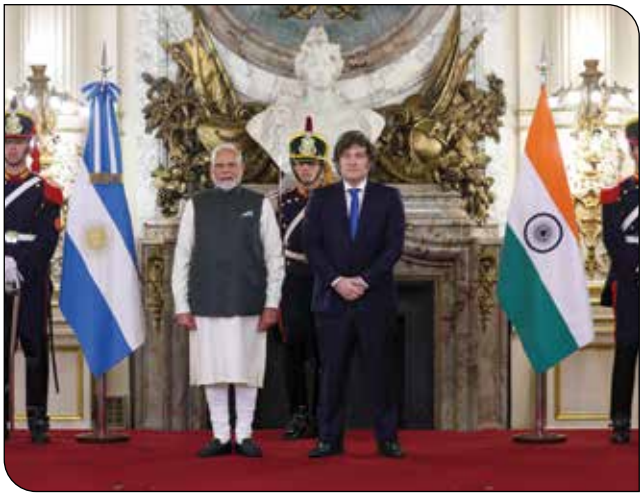

ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में 05 जुलाई, 2025 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति श्री जेवियर माईलेई से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पोर्ट ऑफ स्पेन में 4 जुलाई, 2025 को त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

अकरा (घाना) में 02 जुलाई, 2025 को घाना गणराज्य के राष्ट्रपति श्री जॉन ड्रामानी महामा से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

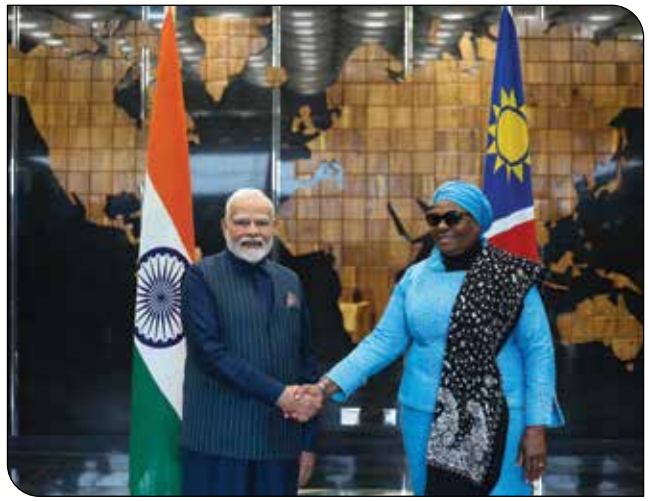

विंडहोक (नामीबिया) में 9 जुलाई, 2025 को नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 21 जुलाई, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

छायाकार: अजय कुमार सिंह